

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 04 Dec , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	गुसाडी नृत्य
Page 05 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	केंद्र ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा
Page 06 Syllabus : GS : 3 : पर्यावरण	विश्व वन्यजीव दिवस पर, भारत की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया
Page 07 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	जब तूफान ज़मीन से गुज़रता है
Page 13 Syllabus : GS 1 : भूगोल	नए संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों से पता चलता है कि सूखे और रेगिस्तानीकरण की भारी कीमत चुकानी पड़ती है
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।	बाकू के 'एनसीक्यूजी परिणाम' पर विचार

It's about quality

गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला गुसाडी नृत्य तेलंगाना के स्वदेशी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

➤ यह तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'प्रजा पालना विजयोत्सव' के समारोह के दौरान किया गया।

Vibrant moves



Claiming success: Artistes from the Gond tribe perform the Gussadi dance during the 'Praja Palana Vijayotsava', to commemorate the completion of one year of the Congress government in Telangana on Tuesday. NAGARA GOPAL

गुसाडी नृत्य: मुख्य जानकारी

- उत्पत्ति: गुसाडी नृत्य गोंड जनजाति का एक पारंपरिक आदिवासी कला रूप है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना के क्षेत्रों में प्रचलित है।
- प्रदर्शन: यह देवताओं और पूर्वजों को श्रद्धांजलि के रूप में फसल के मौसम के बाद मनाए जाने वाले डंडारी त्योहार के दौरान किया जाता है।
- वेशभूषा: नर्तक पंखों वाली टोपी, आभूषण और शरीर पर रंग सहित विस्तृत वेशभूषा पहनते हैं, जो सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी विरासत का प्रतीक है।
- संगीत: ढोल जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ, लयबद्ध धड़कन पैदा करते हुए नृत्य को आगे बढ़ाया जाता है।
- अवसर: आदिवासी कला को बढ़ावा देने के लिए अक्सर त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है।
- मान्यता: भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में गुसाडी नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें नौकरी में आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

➡ ये कदम अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद संवैधानिक सुरक्षा के नुकसान पर चल रहे विरोध के जवाब में उठाए गए हैं।

खबर का विश्लेषण:

- ➡ केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है।
- ➡ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख की पहाड़ी परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का सुझाव दिया गया है।
- ➡ केंद्र ने लद्दाख की भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मसौदा तैयार करने पर काम करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें उर्दू और भोटी को आधिकारिक भाषा घोषित करना शामिल है।
- ➡ लद्दाख में स्थानीय चिंताओं, सशक्तिकरण और वन्यजीव मुद्दों को संबोधित करने के लिए 22 लंबित कानूनों की समीक्षा का प्रस्ताव है।
- ➡ सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकारी पदों के लिए भर्ती तुरंत शुरू होगी, जिसमें राजपत्रित पद जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे।
- ➡ लद्दाख की प्रमुख मांगों में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, जनजातीय दर्जा और लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय सीट शामिल हैं।

Centre proposes 95% govt. job reservation for locals in Ladakh

Vijaita Singh
NEW DELHI

The Union Ministry of Home Affairs (MHA) has proposed 95% reservation in government jobs for locals in Ladakh, one-third reservation for women in hill councils and has agreed to address concerns regarding land-related matters, according to leaders from the region who attended a high-powered committee (HPC) meeting on Tuesday.

The Centre has also proposed to work on a draft to ensure "constitutional safeguards" to preserve the land and culture of Ladakh and also agreed to declare Urdu and Bhoti the official languages of Ladakh. The Ministry proposed to review 22 pending laws to address local concerns, empowerment and wildlife areas.

Ladakh has been protesting for the past five years since it lost constitutional safeguards ensured under Article 370 of the Constitution.

Former BJP MP, Thupstan Chhewang, chairman of the Leh Apex Body (LAB) who attended the talks, said a separate public service commission was not constitutionally possible for Ladakh as the Union Territory did not have a legislature.

Recruitments soon

"The government has assured us that recruitments will start immediately. We said recruitments for gazetted posts should be done through the Jammu and Kashmir Public Service Commission [JKPSC]," Mr. Chhewang said.

"The next meeting is on January 15 where sixth schedule will be discussed," he said.

For the past five years, people in Ladakh have been pressing for four demands – Statehood for Ladakh, inclusion of Ladakh in the sixth schedule of the Constitution, thus giving it a tribal status, job reservation for locals and a Parliamentary seat each for Leh and Kargil.

Page 06: GS : 3 : Environment – Conservation – Important Species

भारत, विश्व के मात्र 2.4% भू-क्षेत्र को कवर करने के बावजूद, वैश्विक जैव-विविधता के एक महत्वपूर्ण भाग का घर है, जो इसे एक महाविविधता वाला देश बनाता है।

On World Wildlife Day, making a clarion call to protect India's critically endangered species

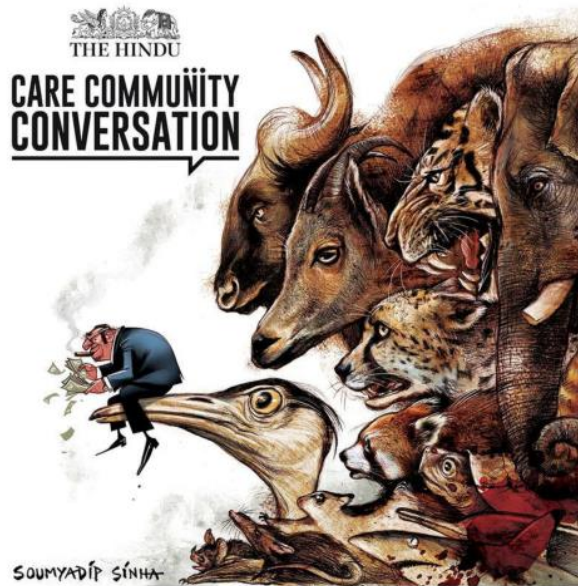
The Hindu Bureau

Despite possessing only 2.4% of the world's land area, India accounts for 7-8% of all recorded species, which includes 45,000 species of plants and 91,000 of animals. This rich biodiversity is one of the reasons that it has been historically identified as a megadiverse country.

World Wildlife Conservation Day (December 4) serves as an occasion to not only celebrate the country's rich biodiversity but also evaluate if enough is being done to protect the critically endangered species that find a home here.

India has 10 biogeographic zones and is home to 8.58% of the mammalian species documented so far, with the corresponding figures for avian species being 13.66%, for reptiles 7.91%, for amphibians 4.66%, for fish 11.72% and for plants 11.8%.

Four of the 34 globally identified biodiversity hotspots, namely the Hima-



layas, Indo-Burma, the Western Ghats-Sri Lanka and Sundaland, are located in India.

With only about 2.4% of the world's total land surface, India punches far above its weight in encompassing the breadth that evolution has to offer. However, the natural bounty is often at odds with India's economic trajectory.

As the most populous country in the world and with 65% of the population aged under 35, India's growth trajectory implies a hunger for natural resources: land, wood, timber, forest produce, precious metals, coal and more. This unfortunately conflicts with wildlife habitat, bringing several species – of the land and air – too close to

comfort with human settlements.

Indian civilisation has absorbed a tolerance, even reverence for several wild animals as is evidenced in its religious mythology. The wildlife reserves and sanctuaries in India, set up to conserve certain endangered species, are unfenced, unlike the big game reserves in Africa and neither is hunting permissible in India as a licensed, recreational sport.

Risk of extinction

However this doesn't imply that India is a haven for wildlife. There are 73 "critically endangered" species in India as of 2022 – the most updated estimates made available by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) classifies species as critically endangered when they are at the highest risk of extinction in the wild. The number of critically endangered species has risen from 47 in

2011, though this also due to improvements in data availability and monitoring and not entirely due to animals of a species getting decimated.

Of the nine species of mammals considered critically endangered, eight are endemic, which means that their habitat is limited to a small geographic area within India. These include the Kashmir stag or Hangul, Malabar large-spotted civet, Andaman Shrew, Jenkin's shrew, Nicobar shrew, Nandapha flying squirrel, large rock rat and Leafletted leaf-nosed bat.

While the carnivores of the cat family – lions, tigers, cheetahs – garner considerable attention because of their appeal to tourism, they are only three on the list of critically endangered animals.

Birds such as the Great Indian Bustard face threats from sources such as powerlines in Rajasthan and often fail to garner the attention they deserve for their conservation.

- हालाँकि, इसकी बढ़ती आबादी और आर्थिक माँगों ने इस जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है, जिससे प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है।
- विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस इन संरक्षण चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

भारत की समृद्ध जैव विविधता

- भारत, दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ, सभी दर्ज प्रजातियों में से 7-8% का घर है।

- ➡ इसमें पौधों की 45,000 प्रजातियाँ और जानवरों की 91,000 प्रजातियाँ शामिल हैं, जो भारत को दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक बनाती हैं।

विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस

- ➡ 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस भारत की जैव विविधता की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- ➡ यह दिन भारत में रहने वाली गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करने का कार्य करता है।

जैवभौगोलिक क्षेत्र और प्रजाति विविधता

- ➡ भारत में 10 जैवभौगोलिक क्षेत्र हैं, जो वैश्विक जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में 8.58% स्तनधारी प्रजातियाँ, 13.66% पक्षी प्रजातियाँ, 7.91% सरीसृप, 4.66% उभयचर, 11.72% मछली प्रजातियाँ और 11.8% पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- ➡ देश में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार हैं: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट-श्रीलंका और सुंदरलैंड।

आर्थिक विकास के साथ टकराव

- ➡ अपनी समृद्ध जैव विविधता के बावजूद, भारत की विकास गति, जो इसकी बड़ी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों की मांग से प्रेरित है, अक्सर वन्यजीव संरक्षण के साथ टकराव करती है।
- ➡ भूमि, लकड़ी, कोयला और अन्य संसाधनों की बढ़ती ज़रूरत वन्यजीवों के आवासों को खतरे में डालती है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष होता है।

भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ

- ➡ वर्ष 2022 तक, भारत में 73 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, जबकि वर्ष 2011 में इनकी संख्या 47 थी।
- ➡ यह वृद्धि आंशिक रूप से बेहतर डेटा उपलब्धता और निगरानी के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) इन प्रजातियों को विलुप्त होने के उच्चतम जोखिम वाले के रूप में वर्गीकृत करता है।

भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ

गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्तनधारी (भारत के लिए स्थानिक)

- ➡ **कश्मीरी बारहसिंगा (हंगुल)**
 - संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
 - निवास स्थान: केवल कश्मीर घाटी में पाया जाता है।
 - खतरे: निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार और शिकार की उपलब्धता में कमी।
 - जनसंख्या: जंगली में 200 से कम व्यक्ति होने का अनुमान है।
- ➡ **मालाबार लार्ज-स्पॉटेड सिवेट**
 - संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट) निवास स्थान: भारत में पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक।
 - खतरे: आवास का विनाश, इसके फर के लिए शिकार, तथा शिकार का नुकसान।
 - जनसंख्या: माना जाता है कि जनसंख्या बहुत छोटी तथा विखंडित है।
- ➡ **अंडमान शू**
 - संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
 - आवास: अंडमान द्वीप समूह के लिए स्थानिक।
 - खतरे: वनों की कटाई, आक्रामक प्रजातियों द्वारा शिकार के कारण आवास का नुकसान।

○ जनसंख्या: अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, लेकिन बहुत कम होने की संभावना है।

➔ **जेनकिन्स शू**

- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
- आवास: भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक, पृथक क्षेत्रों में पाया जाता है।
- खतरे: आवास क्षरण तथा सीमित क्षेत्र।
- जनसंख्या: बहुत छोटी, विखंडित आबादी।

➔ **निकोबार शू**

- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
- आवास: निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।
- खतरे: आवास का नुकसान, मानव अतिक्रमण, तथा आक्रामक प्रजातियाँ।
- जनसंख्या: बहुत कम और कुछ खास द्वीपों तक सीमित।

➔ **नमदफा उड़ने वाली गिलहरी**

- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
- निवास स्थान: अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
- खतरे: वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियों के कारण निवास स्थान का नुकसान।
- जनसंख्या: छोटी और एक खास क्षेत्र तक सीमित।

➔ **बड़ा चट्टानी चूहा**

- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
- निवास स्थान: भारत के चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- खतरे: निवास स्थान का विनाश और सीमित क्षेत्र।
- जनसंख्या: बहुत कम और खास चट्टानी क्षेत्रों तक सीमित।

➔ **लीफलेटिड लीफ-नोज्ड बैट**

- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट)
- निवास स्थान: भारत में खास गुफाओं और चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- खतरे: निवास स्थान में गड़बड़ी, खास तौर पर गुफाओं का विनाश और बसेरा स्थल का नुकसान।
- जनसंख्या: बेहद सीमित और खंडित।

गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी

➔ **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड**

- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (IUCN रेड लिस्ट)
- निवास स्थान: राजस्थान और भारत के कुछ अन्य भागों में पाया जाता है।
- खतरे: कृषि विस्तार, बिजली लाइनों और शिकार के कारण निवास स्थान का नुकसान।
- जनसंख्या: अनुमानतः 150 से कम व्यक्ति, मुख्यतः राजस्थान में।

निष्कर्ष

- ➔ वन्यजीवों के प्रति भारत की ऐतिहासिक श्रद्धा के बावजूद, इसकी जैव विविधता खतरे में है, मानवीय गतिविधियों और निवास स्थान के नुकसान के कारण कई प्रजातियाँ विलुप्त होने का सामना कर रही हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: तीव्र आर्थिक विकास और बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच अपनी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें। इन मुद्दों को संबोधित करने में सरकार और समाज की भूमिका पर चर्चा करें। (250 Words /15 marks)

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जीवनचक्र में लैंडफॉल एक महत्वपूर्ण घटना है, जो तब होती है जब इसका केंद्र भूमि पर चला जाता है, जिससे नमी खोने के कारण तूफान कमजोर हो जाता है।

➡ यह क्षण तूफानी लहरों और तेज़ हवाओं के कारण महत्वपूर्ण क्षति का कारण बन सकता है।

QUESTION CORNER

When a storm passes over land



Q: What is landfall?

A: Once it's fully formed, a tropical cyclone (in the northern

hemisphere) has a complex 3D structure. Two important parts of it are the eye and the eyewall. The eye is the centre around which the cyclone rotates. It consists of cold air descending from the cyclone's top with warm air rising in a spiral around it. The eyewall consists of high thunderstorms that bring rain, lightning, and powerful winds.

As long as the cyclone moves over water, it can draw more moisture from below to produce new clouds and rain events around it. But when the storm crosses over onto land, its moisture supply declines drastically, and the cyclone weakens.

Landfall is the moment in a tropical cyclone's life when its eye moves over land. Stormy weather brought by a cyclone is stronger around the eye, and landfall events can be deadly because they expose human settlements on land to strong winds and heavy rain. Their effects can be compounded by storm



Tidal waves triggered by Cyclone Fengal lashed the R.K. Beach in Visakhapatnam on November 30. DEEPAK K.R.

surges that flood coastal areas and prevent inland areas from draining normally.

If the air over land is drier, among other factors, a cyclone weakens quickly after landfall. Depending on environmental conditions, it may dissipate completely, or it could pass over land and re-emerge on the other side. In 2021, Cyclone Gulab made landfall over coastal Andhra Pradesh, weakened as it moved across peninsular India, and re-emerged four days later as Cyclone Shaheen in the Arabian Sea.

- The Hindu Bureau

For feedback and suggestions

for 'Science', please write to
science@thehindu.co.in
with the subject 'Daily page'

चक्रवात का लैंडफॉल क्या होता है?

- लैंडफॉल की परिभाषा: लैंडफॉल तब होता है जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख जमीन पर चलती है, जो तूफान के लिए समुद्र से जमीन की ओर बदलाव को चिह्नित करता है।
- चक्रवात की संरचना: एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आंख होती है, जो एक शांत केंद्र होता है, और आईवॉल, जो भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली के साथ गरज के साथ बनी होती है।
- पानी के ऊपर नमी की आपूर्ति: समुद्र के ऊपर होने पर, चक्रवात पानी की सतह से नमी खींच सकते हैं, जो तूफान के विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें नए बादल बनना और बारिश शामिल है।
- भूमि से कमजोर होना: जब चक्रवात भूमि पर आता है, तो यह अपनी प्राथमिक नमी की आपूर्ति खो देता है और वाष्पीकरण और ठंडा होने के कारण कमजोर पड़ने लगता है।
- तूफानी लहरें: चक्रवात तूफानी लहरें ला सकते हैं, जो तटीय बाढ़ का कारण बनते हैं और अंतर्देशीय क्षेत्रों में जल निकासी को बाधित करते हैं।
- लैंडफॉल के बाद का व्यवहार: लैंडफॉल के बाद, पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर, चक्रवात जल्दी से कमजोर हो सकता है, फैल सकता है या समुद्र के ऊपर फिर से उभर सकता है। उदाहरण के लिए, चक्रवात गुलाब 2021 में भूस्खलन के बाद कमजोर हो गया लेकिन चक्रवात शाहीन के रूप में फिर से उभरा।

रियाद में UNCCD COP16 शिखर सम्मेलन रेगिस्तानीकरण से निपटने और जल की कमी को दूर करने पर केंद्रित है, जिसमें सूखे से होने वाला वैश्विक नुकसान अब सालाना 307 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भूमि बहाली और सूखे से निपटने की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना है, जिसमें प्रकृति आधारित समाधानों और संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश पर जोर दिया जाएगा।

New UN figures reveal huge cost of drought, desertification

Reuters
LONDON

In a year when extreme heat triggered droughts from southern Africa to South America, world leaders are meeting in Riyadh in Saudi Arabia this month to thrash out ways of tackling desertification and water scarcity.

UN Secretary-General Antonio Guterres has called the summit - the 16th Conference of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD COP16) - a "moonshot moment" to accelerate action on land and drought resilience as some estimates predicted trillions of dollars would be needed to tackle the problem.

As the talks kicked off, a

new report showed global losses from drought cost \$307 billion a year.

The report, released Tuesday by UNCCD and the UN University Institute for Water, Environment, and Health UNU-INWEH, puts the cost much higher than previously believed because earlier calculations focused on agriculture, overlooking the wider consequences on health and energy sectors.

Up to 40% of the world's land is degraded, droughts are becoming more frequent and severe, increasing by 29% since 2000 due to climate change and unsustainable land management, the UN says.

This threatens agriculture, water security, and livelihoods of 1.8 billion people, with the poorest



Parched land: COP16 had the largest-ever attendance of any UN land, drought talks to date. REUTERS

nations bearing the brunt.

Scientists say drought worsens water and air quality and intensifies sand and dust storms, causing respiratory illness

es and disrupting electricity grids. It can also harm food supplies when rivers dry up or food production becomes impossible because of water shortages.

Ibrahim Thiaw, the executive secretary of the UNCCD, said the summit should promote healthy lands and drought resilience to ensure food and

energy security, human development and peace.

He said this COP16 had the largest-ever attendance, including delegates from the private sector and civil society, of any UN land and drought talks to date.

"Achieving land and drought goals is essential to meet the global climate and biodiversity targets," Thiaw told the Thomson Reuters Foundation in an interview via email.

The Riyadh summit comes after UN talks on biodiversity in Colombia in October and COP29 in Azerbaijan in November with the question of who pays to stem the worst effects of climate change taking centre-stage.

The Riyadh conference aims to accelerate investment and action in

drought resilience and land restoration, building on agreements negotiated during the last summit in Ivory Coast in 2022.

"Given the urgency of the challenge, the gravity of the impacts, and the unique opportunity before us, I call on all parties to rise their ambition and solidarity for our lands and our future," Thiaw said.

As talks began, host and oil producer Saudi Arabia announced the creation of the Riyadh Global Drought Resilience Partnership that will leverage public and private finance to support 80 of the most vulnerable and drought-hit countries around the world.

An initial \$2.15 billion has been pledged to the partnership by Saudi Arabia, the Islamic Develop-

ment Bank and the OPEC Fund for International Development.

Nature-based solutions
The new UNCCD report said nature-based solutions, including planting trees, managing livestock grazing and creating green spaces in cities, offered cost-effective ways to combat drought.

The research found investment in natural capital - the world's natural resources - offered returns of \$1.40 to \$2.70 for every dollar spent in two years.

Such investments could include restoring and improving the health of soil so it can hold more water by, for example, using organic fertilisers and preventing nutrient depletion by rotating crops.

वैश्विक संदर्भ और तात्कालिकता

- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD COP16) के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में हो रहा है, जहाँ विश्व के नेता अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण होने वाले मरुस्थलीकरण और पानी की कमी के समाधान पर चर्चा कर रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस शिखर सम्मेलन को एक "मूनशॉट मोमेंट" के रूप में वर्णित किया, जिसका उद्देश्य भूमि और सूखे के प्रति तन्यकता को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाना है।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि बढ़ते संकट से निपटने के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता होगी।

सूखे और मरुस्थलीकरण की लागत

- एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि सूखे के कारण वैश्विक नुकसान की लागत सालाना 307 बिलियन डॉलर है, जो पिछले अनुमानों की तुलना में काफी अधिक है।
- पहले की गणना मुख्य रूप से कृषि नुकसान पर केंद्रित थी, लेकिन स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया, जिससे आर्थिक नुकसान की अधिक व्यापक समझ बन गई।

मरुस्थलीकरण और सूखे का प्रभाव

- संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, और जलवायु परिवर्तन तथा असंवहनीय भूमि प्रबंधन के कारण वर्ष 2000 से 29% की वृद्धि के साथ, सूखे की घटनाएं लगातार और गंभीर होती जा रही हैं।
- ये मुद्दे कृषि, जल सुरक्षा और 1.8 बिलियन लोगों, विशेष रूप से सबसे गरीब देशों की आजीविका को खतरे में डालते हैं।
- सूखे से हवा और पानी की गुणवत्ता खराब होती है, रेत और धूल के तूफान तेज होते हैं, और बिजली ग्रिड बाधित होते हैं।
- यह खाद्य उत्पादन को भी प्रभावित करता है, जिससे नदियों के सूखने और पानी की कमी होने पर कमी होती है।

शिखर सम्मेलन के लक्ष्य और निवेश

- ➡ यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव ने इस बात पर जोर दिया कि शिखर सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, मानव विकास और शांति सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ भूमि और सूखे के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- ➡ सऊदी अरब ने सऊदी अरब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक फंड से \$2.15 बिलियन की प्रारंभिक प्रतिज्ञा के साथ, सबसे अधिक सूखा प्रभावित 80 देशों का समर्थन करने के लिए रियाद वैश्विक सूखा लचीलापन भागीदारी की घोषणा की।

प्रकृति-आधारित समाधान

- ➡ UNCCD रिपोर्ट ने प्रकृति-आधारित समाधानों पर प्रकाश डाला, जैसे कि पेड़ लगाना, चराई का प्रबंधन करना और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान बनाना, सूखे से निपटने के लिए लागत-प्रभावी तरीकों के रूप में।
- ➡ प्राकृतिक पूंजी में निवेश, जैसे कि मिट्टी की बहाली, ने उच्च रिटर्न दिखाया है, जो दो वर्षों में खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए \$1.40 से \$27 तक है।

मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

- ➡ मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD): 1994 में स्थापित, इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और सूखे के प्रभावों को कम करना है।
- ➡ उद्देश्य: मुख्य रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ➡ मिशन: संधारणीय भूमि प्रबंधन (SLM) प्रथाओं को बढ़ावा देना, क्षरित भूमि को बहाल करना और मरुस्थलीकरण के प्रभावों को कम करना।
- ➡ सदस्यता: अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य देशों सहित 197 पक्ष।
- ➡ मुख्य फोकस क्षेत्र: संधारणीय भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना। साझेदारी और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना। सामुदायिक लचीलापन को मजबूत करना।
- ➡ रणनीतिक कार्यवाहियाँ: प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रमों (NAP) का कार्यान्वयन, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण।
- ➡ वैश्विक लक्ष्य: 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: मरुस्थलीकरण और सूखे के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें। प्रकृति-आधारित समाधान इन मुद्दों से निपटने में कैसे योगदान दे सकते हैं, और मरुस्थलीकरण और जल की कमी से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी क्या भूमिका निभाती है? (250 Words /15 marks)

PIB- In News : Maritime India Vision 2030

MIV 2030 एक व्यापक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र का समग्र विकास करना है।

- ➡ इसमें भारत को वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 150 पहलों की रूपरेखा दी गई है।
- ➡ इस रूपरेखा में बंदरगाह अवसंरचना, रसद, जहाज निर्माण, तटीय यातायात, नवाचार, स्थिरता और वैश्विक सहयोग सहित 10 विषयों को शामिल किया गया है।

मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030: अवलोकन

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
GOVERNMENT OF INDIA
मेरी सरकार

FURTHERING INDIA'S MARITIME ECONOMY

MARITIME INDIA VISION 2030

KEY TALKING POINTS

- To develop waterways for urban transportation, thereby decongesting cities
 - Aims to ferry annual passenger capacity of 70 crore against 14 crore presently
- Improving private sector participation
 - To increase the cargo handled at major ports to over 85% vs 51% in 2020
 - Active promotion of involvement of private sector in development and operations of ferry & RoRo terminals
- Development of Green Sustainable Ports to increase the share of renewable energy to over 60% by 2030 from less than 10% presently
 - Reach the target of Zero Accident Ports by 2022
- Make in India, Make for the world
 - Become a leading ship building nation by 2030
- Set-up a maritime development fund to provide low cost, long-term funding to maritime sector stakeholders

समुद्री क्षेत्र में प्रगति (2022-2024)

- बंदरगाह क्षमता: 1598 एमएमटीपीए (वित्त वर्ष 2022) से बढ़कर 1630 एमएमटीपीए (वित्त वर्ष 2024) हो गई।
- पोत टर्न अराउंड टाइम (टीएटी): 53 घंटे (वित्त वर्ष 2022) से घटकर 48 घंटे (वित्त वर्ष 2024) हो गया।
- जहाज बर्थ डे आउटपुट: 16,000 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 2022) से बढ़कर 18,900 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 2024) हो गया।
- वैश्विक मान्यता: दो भारतीय बंदरगाह वैश्विक शीर्ष 30 बंदरगाहों में शामिल हैं।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई): 44 (2018) से 22 (2023) तक की रैंकिंग में सुधार हुआ।
- राष्ट्रीय जलमार्ग कार्गो वॉल्यूम: 108 एमएमटी (वित्त वर्ष 2022) से बढ़कर 133 एमएमटी (वित्त वर्ष 2024) हो गया।
- तटीय टन भार: 260 एमएमटी (वित्त वर्ष 2022) से बढ़कर 324 एमएमटी (वित्त वर्ष 2024) हो गया।

वित्तीय निवेश

- पूंजीगत व्यय: ₹5527 करोड़ (वित्त वर्ष 2022) से 37% बढ़कर ₹7571 करोड़ (वित्त वर्ष 2024) हो गया।
- सकल बजट सहायता (जीबीएस): ₹1099 करोड़ (वित्त वर्ष 2022) से 54% बढ़कर ₹1687 करोड़ (वित्त वर्ष 2024) हो गया।
- बंदरगाह विकास परियोजनाएँ: 75 परियोजनाएँ प्रदान की गईं, जिससे कार्गो हैंडलिंग और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई।

समुद्री व्यापार और रोजगार पर प्रभाव

- बंदरगाह यातायात: 720 एमएमटी (वित्त वर्ष 2022) से बढ़कर 820 एमएमटी (वित्त वर्ष 2024) हो गया।
- रोजगार सृजन: कार्गो हैंडलिंग, बुनियादी ढाँचे और कूज पर्यटन में वृद्धि ने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा किए।

निगरानी तंत्र

- सागर मंथन पोर्टल: प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, परियोजनाओं और दीर्घकालिक रणनीतियों को ट्रैक करता है।
- विभास और नाविक प्रकोष्ठ: MIV उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकिंग, विचार और नवाचार की सुविधा प्रदान करते हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे और व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030 के महत्व पर चर्चा करें। इसने इस क्षेत्र में रोजगार सृजन और सतत विकास में किस तरह योगदान दिया है? (150 Words /10 marks).

—It's about quality—

Page : 08 Editorial Analysis

Reflections on Baku's 'NCQG outcome'

The urgency of climate change has never been more evident. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has highlighted the need for significantly stronger commitments to limit global warming to 1.5°C above pre-industrial levels. Current policies, if continued globally, are expected to lead to a temperature rise of up to 3.1°C. The increasingly visible impacts of climate change across geographies, apart from the growing body of scientific evidence, serve as a constant reminder of the need to accelerate climate action. Cleaner fuels and technological solutions are emerging across sectors and could be increasingly accessed and deployed with adequate focus on the means of implementation.

Against this backdrop with COP 29 (in Baku, Azerbaijan, in November 2024) branded as the "Finance COP", the hope was to see an ambitious outcome (specifically related to the NCQG or New Collective Quantified Goal) which strongly supported this understanding.

Financing needs of the developing world

Finance is a critical component in accelerating the adoption of cleaner alternatives, especially in developing countries. While some of the renewable technologies pay off in the long run due to lower fuel and operational costs, the upfront costs of some of these technologies are much higher than the current options requiring government support to ensure affordability at the consumer end. Other green technologies may still be evolving and are associated with risks of failure that front-runners may need to bear. Given the pressure on government resources that need to be prioritised towards development activities, additional finance must be up-scaled urgently within this decade if transformational changes are to be expected in the adoption of clean and efficient alternatives in developing countries, as access to modern energy and infrastructure improves.

India's expenditure on green energy schemes encompass a wide range of initiatives aimed at expanding renewable energy infrastructure, promoting energy efficiency and clean fuel and technology innovations as part of its commitment to global climate goals. MNRE received its highest ever allocation of ₹19,100 crore in the Budget 2024-25, apart from about ₹40 crore being allocated for enhancing energy efficiency. In the transport sector, a subsidy of ₹5,790 crore has been provided to electric vehicle manufacturers under phase-II of Faster Adoption and



Ritu Mathur

Director, Energy Assessment and Modelling, TERI



Sanchit Saran Agarwal

Associate Fellow, Energy Assessment and Modelling, TERI

It appears to have bypassed the principles of equitable burden sharing and climate justice, having failed to have recognised the financial needs of the global south

Manufacturing of (Hybrid) Electric vehicles (FAME) scheme.

Another aspect of finance required for the transition relates to the source and type of finance. There are growing concerns regarding fiscal debt, which forms the basis of the ask, for part of the financial support from developed countries to be in the form of public grants rather than loans.

The pace and the scale of transitions are also affected by the higher cost of capital in developing countries. Financial flows from developed countries must ideally aim to strengthen fiscal capacities and enable the unlocking of financial markets in developing countries to support and accelerate their climate action. The use of debt instruments to access finance does not work well for developing countries since their high debt burdens limit their ability to successfully incentivise domestic private capital for climate action. It is well recognised that developing countries attract much higher lending rates as compared to developed countries and much of the global financial flows are restricted within the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries. Therefore, ensuring the flow of climate finance to developing countries at affordable lending rates is important.

Role of the NCQG

At Cancun, in 2010, developed countries had pledged to provide \$100 billion annually upto 2020. Further, at COP21 in Paris, the parties decided to establish an NCQG prior to 2025, with the Cancun commitment as the base point. The rationale for establishing the NCQG was pressing. The existing climate pledges have generally been criticised for their lack of specificity and accountability.

Therefore, the NCQG was intended to create a framework for shared climate goals, to establish clear and quantified objectives that nations could aim to achieve, with transparency and accountability at the forefront. At COP26 at Glasgow in 2021, an ad hoc work programme for NCQG discussions was established to run from 2022-24, culminating towards the discussions at COP29.

The Second Needs Determination Report by the Standing Committee on Finance under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) estimated that

between \$5 trillion to \$7 trillion would be needed by 2030 to meet half the needs of 98 countries. Developing countries had put forward a conservative ask of \$1.3 trillion annually at COP 29 (largely from public sources to enable leveraging the rest through private finance).

However, the developed world has in the NCQG agreed to provide an abysmal figure of \$300 billion annually till 2035. This quantum is not only miniscule but hardly represents any major change in real flows – probably a target that could be achieved even with current or minimally additional efforts, if we account for inflation. Further, the mobilisation of funds is expected through all sources of finance including private capital. Undoubtedly,

therefore, there is disappointment with the NCQG outcome, both on the quantum and structure of finance since it does not support the narrative of transformative action. While the decision to triple the flow of public resources through various operating entities of the Financial Mechanism, the Adaptation Fund, the Least Developed Countries Fund, and the Special Climate Change Fund from the 2023 level by 2035 is a positive aspect, it could also see rather slow progress in the next few years (and not aligned to the narrative of the urgency in climate action).

The road ahead

COP29 saw the finance commitment step up from the earlier commitment of \$100 billion a year to \$300 billion a year. While this is a step in the correct direction, it is clearly not as ambitious as expected given that climate change is clearly recognised as one of the greatest threats and challenges of our time. Overall, the NCQG outcome is rather disappointing and does not seem to have aligned well with the very core of why the goal was set up in the first place. It clearly bypasses the principles of equitable burden sharing and climate justice as it fails to recognise the financial needs of the global south.

The way forward is to keep the talks ongoing. Climate change has no geographical boundaries. Thus, it is imperative that the international community cooperates towards the global good, keeping climate justice at the core and respecting the principles of the Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR and RC). Developing countries must stick together and ensure that any transition is just and fair in the real sense.



GS Paper 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-3 2021): जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। इस सम्मेलन में भारत द्वारा क्या प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गईं? (250 words/15m)

UPSC Mains Practice Question: ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने में न्यायसंगत जलवायु वित्त के महत्व पर चर्चा करें। जलवायु न्याय और विकासशील देशों की ज़रूरतों के संदर्भ में COP29 के परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 Words /15 marks)

संदर्भ:

- लेख में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें समतापूर्ण जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- COP29 चर्चाएँ नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर केंद्रित थीं, लेकिन अपर्याप्त प्रतिबद्धताएँ प्रदान की गईं, जो विकासशील देशों की अपेक्षाओं से कम थीं।
- यह जलवायु न्याय प्राप्त करने में लगातार चुनौतियों को रेखांकित करता है।

जलवायु कार्रवाई और COP29 की तात्कालिकता

- IPCC ने वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया है।
- यदि वर्तमान नीतियाँ जारी रहें, तो तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे दुनिया भर में जलवायु प्रभाव तीव्र हो सकते हैं।
- बाकू, अज़रबैजान (नवंबर 2024) में COP29, जिसे "वित्त COP" के रूप में ब्रांडेड किया गया, जलवायु वित्त चर्चाओं, विशेष रूप से नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर केंद्रित था।

विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त का महत्व

- उच्च प्रारंभिक लागत: अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए अक्सर कम ईंधन और परिचालन लागत जैसे दीर्घकालिक लाभों के बावजूद महत्वपूर्ण प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है।
- तकनीकी जोखिम: कई हरित प्रौद्योगिकियाँ अभी भी विकसित हो रही हैं, जिससे जोखिम पैदा हो रहे हैं, जिन्हें शुरुआती अपनाने वालों को उठाना होगा।
- सीमित सरकारी संसाधन: विकासशील देशों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएँ विकासात्मक गतिविधियों पर केंद्रित होती हैं, जिसके लिए बाहरी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

भारत की हरित ऊर्जा पहल

- भारत ने 2024-25 के बजट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को ₹19,100 करोड़ आवंटित किए, जो मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे अधिक है।

- ▶ FAME योजना के दूसरे चरण के तहत ₹5,790 करोड़ की सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं का समर्थन करती है।
- ▶ इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता पहलों के लिए ₹40 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

जलवायु वित्त पहुँच में चुनौतियाँ

- ▶ ऋण का बोझ: विकासशील देश वित्तीय ऋण चुनौतियों को बढ़ाने से बचने के लिए ऋण के बजाय अनुदान को प्राथमिकता देते हैं।
- ▶ उच्च उधार लागत: विकासशील देशों को असमान रूप से उच्च उधार लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे जलवायु कार्रवाई के लिए निजी पूंजी जुटाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- ▶ OECD पूर्वाग्रह: वित्तीय प्रवाह मुख्य रूप से विकसित देशों की ओर निर्देशित होते हैं, जिससे विकासशील देशों के लिए किफायती वित्तपोषण सीमित हो जाता है।

NCQG की भूमिका और लक्ष्य

- ▶ NCQG की स्थापना कैनकन प्रतिबद्धता (2010) के भाग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर प्रदान करना था और बाद में पेरिस में COP21 में इसे सुदृढ़ किया गया।
- ▶ इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्पष्ट, परिमाणित जलवायु वित्त उद्देश्य प्रदान करना है।
- ▶ UNFCCC की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 5-7 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी, जिसमें विकासशील देश अपनी जलवायु वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का अनुरोध करेंगे।

COP29 में NCQG का निराशाजनक परिणाम

- ▶ विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर देने का वचन दिया, जो विकासशील देशों द्वारा अनुरोधित 1.3 ट्रिलियन डॉलर से बहुत कम है।
- ▶ प्रतिबद्धता मुख्य रूप से निजी पूंजी सहित सभी वित्तीय स्रोतों से धन जुटाने पर निर्भर करती है।
- ▶ जबकि 2035 तक अनुकूलन निधि जैसे तंत्रों के माध्यम से सार्वजनिक संसाधन प्रवाह को तीन गुना करने का निर्णय सकारात्मक है, जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता को संबोधित करने के लिए प्रगति बहुत धीमी हो सकती है।

जलवायु न्याय के लिए एक बाधा के रूप में वित्त

- ▶ NCQG परिणाम अपर्याप्त महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और न्यायसंगत बोझ-साझाकरण और जलवायु न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
- ▶ यह वैश्विक दक्षिण की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है, जो परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

आगे का रास्ता

- ▶ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैश्विक भलाई के लिए सहयोग पर जोर देते हुए जलवायु वित्त चर्चा जारी रखनी चाहिए।
- ▶ साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों को न्यायसंगत परिवर्तनों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- ▶ सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों को न्यायसंगत और निष्पक्ष वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए एकजुट होना चाहिए।